हूं। जब मैं अपने क्षेत्र में रहता हूं, जिले में रहता हूं, प्रदेश में रहता हूं, तो प्रत्येक दिन लोगों की बातें मेरे पास आती हैं और मैं देखता हूं कि पत्र लिखने के बावजूद भी, यात्रियों का ट्रेन में जाना कंफर्म नहीं हो पाता है। चूंकि यह सस्ती यात्रा है, सुलभ यात्रा है, आज के दिन में अच्छी यात्रा हो रही है, इसलिए गाँव, गरीब, किसान, मजदूर, शोषित, वंचित, सभी समाज, सभी वर्ग के अधिकांश लोग ट्रेन की यात्रा को पसंद करते हैं। परंतु, यात्रियों की जितनी संख्या बढ़ गई है, उतनी बोगियां नहीं मिल पा रही हैं और बोगियां नहीं मिलने के कारण, जितनी यात्रा लोगों को करनी चाहिए, वे नहीं कर पा रहे हैं और टिकट कन्फर्म नहीं हो पा रही हैं। मैं आपके माध्यम से रेल मंत्री जी से आग्रह करना चाहता हूं कि अधिक से अधिक स्लीपर क्लास की बोगियां जोड़ने की कृपा की जाए, जिससे कि यात्री, गाँव के लोग उसमें सफलतापूर्वक, सुविधाजनक तरीके से यात्रा कर सकें। महोदय, मेरा यही आग्रह है।

MR. DEPUTY CHAIRMAN: The following hon. Members associated themselves with the matter raised by hon. Member, Shri Aditya Prasad: Dr. Sasmit Patra (Odisha), Dr. Fauzia Khan (Maharashtra), Shrimati Sangeeta Yadav (Uttar Pradesh), Dr. Kalpana Saini (Uttarakhand), Shrimati Geeta alias Chandraprabha (Uttar Pradesh) and Dr. John Brittas (Kerala).

Provision of housing facilities to athletes

श्री संजय सेठ (उत्तर प्रदेश): सर, सबसे पहले तो मैं उन 117 खिलाड़ियों को शुभकामनाएं देता हूँ, जो अभी पेरिस जा रहे हैं और मेरा विश्वास है कि वे बहुत अधिक संख्या में मेडल जीतकर वापस आएंगे। मैं सरकार को धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने इस साल खेल मंत्रालय को 3,442 करोड़ रुपये का बजट दिया है और हमारी सरकार ने पहली बार राष्ट्रीय शिक्षा नीति के माध्यम से, स्पोर्ट्स को एक सब्जैक्ट का दर्जा दिया है। मणिपुर में इसके लिए देश के पहले राष्ट्रीय स्पोर्ट्स विश्वविद्यालय की स्थापना भी हुई है। महोदय, मैं सदन के समक्ष एक बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा उठाना चाहता हूँ, जो हमारे खिलाड़ियों से संबंधित है। खेलो इंडिया योजना के माध्यम से, सरकार ग्रामीण और जमीनी स्तर पर स्पोर्ट इन्फ्रास्ट्रक्चर को सुधारने का काम पूरी शिद्दत से कर रही है और इन योजनाओं की वजह से ग्रामीण इलाकों में भी प्रतिभाशाली युवा देश का नाम राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर रोशन कर रहे हैं। इस योजना के तहत, 32 खेलो इंडिया राज्य उत्कृष्टता केंद्र और 1,059 खेलो इंडिया केंद्रों की स्थापना दी जा रही है। आज पूरे देश में विश्वस्तरीय इन्फ्रास्ट्रक्चर, जैसे स्टेडियम, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, स्पोर्ट्स ग्राउंड हर जिले में बनाए जा रहे हैं तथा हमारे खिलाड़ियों का समर्थन करने के लिए भारत सरकार ने पेरिस में आगामी ग्रामीण खेलो के लिए भारत की तैयारी पर 16 खेल विदाओं पर 470 करोड़ रुपये से अधिक खर्च किए हैं। हमारे खिलाड़ियों के पास खेल संबंधित सारी सुविधाएं मौजूद हैं, लेकिन जो सबसे बड़ी असुविधा का इन्हें सामना करना पड़ रहा है, वह आवास की है। आज ग्रामीण और गरीब परिवार से आने वाले बच्चों के प्रशिक्षण के लिए उन्हें शहर आना पड़ता है और वे या

तो किराये पर मकान लेते हैं या स्पोर्ट्स होस्टल में उन्हें जगह मिलती है। यहाँ कभी-कभी उन्हें बहुत परेशानी का सामना करना पड़ता है और इससे सबसे ज्यादा महिलाओं को असुविधा होती है। मैं सरकार से यह माँग करता हूँ कि जिस प्रकार से प्रधानमंत्री आवास योजना के माध्यम से अफोर्डेबल हाउसिंग को बढ़ावा दिया गया है, उसी प्रकार से खिलाड़ियों के प्रोत्साहन हेतु एक आवास योजना शुरू की जाए, जिससे हर जिले में हमारे एथलीट्स को आवास की सुविधा मिले और वे बेहतर तरीके से परीक्षण प्राप्त करके, देश का नाम रोशन करें। आवास परियोजनाएं स्थानीय अर्थव्यवस्था को भी बढ़ावा दे सकती हैं। 2014 से सरकार देश के खिलाड़ियों के कल्याण पर ध्यान केंद्रित कर रही है और यह उसी दिशा का एक महत्वपूर्ण कदम होगा, धन्यवाद।

MR. DEPUTY CHAIRMAN: The following hon. Members associated themselves with the matter raised by hon. Membe, Shri Sanjay Seth: Shrimati Sulata Deo (Odisha), Shri M. Mohamed Abdulla (Tamil Nadu), Dr. Sasmit Patra (Odisha), Dr. Fauzia Khan (Maharashtra), Dr. Kanimozhi NVN Somu (Tamil Nadu), Dr. John Brittas (Kerala) and Shri Dhananjay Bhimrao Mahadik (Maharashtra).

Concern over dip in India's childhood immunisation numbers

श्री प्रमोद तिवारी (राजस्थान) : महोदय, विश्व स्वास्थ्य संगठन और यूनिसेफ ने अपनी वैश्विक टीकाकरण रिपोर्ट में कहा है कि भारत का बाल टीकाकरण स्तर अभी भी महामारी पूर्व चरण तक नहीं पहुंचा है, क्योंकि राष्ट्रीय कार्यक्रम में 2023 में 16 लाख बच्चों को डीपीटी और खसरे की खुराक नहीं दी गई है। यह एक गंभीर मामला है। 2023 में 1.6 मिलियन शून्य खुराक वाले बच्चे 2022 की तुलना में 45 प्रतिशत अधिक हैं। संयुक्त राष्ट्र की दो एजेन्सियों ने यह भी चिंता व्यक्त की है कि भारत उन 52 देशों में एक है, जहां सर्वाइकल कैंसर होने के बावजूद टीकाकरण पैकेज में एचपीवी टीकाकरण को शामिल नहीं किया गया है। सर्वाइकल कैंसर महिलाओं में कैंसर का दूसरा सबसे बड़ा कारण है। महिलाओं में होने वाला लगभग 18 प्रतिशत कैंसर सर्वाइकल कैंसर के कारण है। मान्यवर, शून्य खुराक वाले बच्चों के मामले में यह बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। शून्य खुराक वाले बच्चों के मामले में भारत नाइजीरिया, कांगो, इथोपिया, सूडान और पाकिस्तान सहित दुनिया के सबसे 10 खराब देशों में एक है। एक तरफ 2012 में एक दिन 19 फरवरी में यूपीए 2 की सरकार में 17 करोड़ से ज्यादा बच्चों का जब पोलिया टीकाकरण हुआ था, तो दुनिया ने सराहा था। आज हम 10 सबसे खराब देशों में आ गए हैं। टीके के मामले में भी हमें चयन करना पड़ेगा। जब कोविड हुआ था, तो उस समय श्री राहुल गांधी या विपक्ष के बहुत से नेताओं ने यह सलाह दी थी कि एस्ट्राजेनेका की जो कोविशील्ड है, वह अभी टैस्टेड नहीं है, उसको न लगवाया जाए, लेकिन लंदन में कोर्ट में कंपनी ने यह स्वीकार किया है कि इससे सडन डेथ के मामले रिपोर्ट हो रहे हैं। जहां इन्हें एक तरफ इस बात का ध्यान रखना है, यह अलग बात है कि पूनावाला ने 52 करोड़ रुपये इनके इलेक्टोरल...